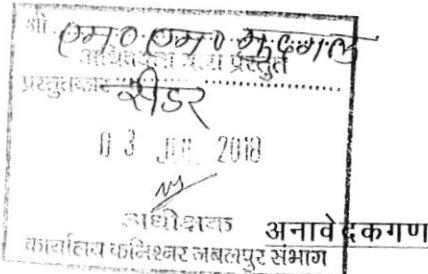




समक्ष माननीय न्यायालय राजस्व मंडल म.प्र. गवालियर

(622)

आवेदिका



प्रकरण क्र.
अन्वरानी - ४७५९/२०१८/जबलपुर/भू.२)

- श्रीमती रंजनी कुमारी पत्नी योगेन्द्र कुमार कुशवाहा, उम्र लगभग 38 वर्ष, निवासी— ग्राम शिवपुरी कजरवारा तहसील व जिला जबलपुर

विरुद्ध

- 1. रामप्रवेश सिंह आत्मज शिवलखन सिंह यादव निवासी— शिवपुरी कजरवारा कटियाघाट रोड तहसील व जिला जबलपुर हाल पता— मोहनी होम्स, बिलहरी, जबलपुर
- 2. मध्यप्रदेश शासन
द्वारा—नायब तहसीलदार (केन्ट क्षेत्र) कलेक्ट्रेट कार्यालय, तहसील व जिला जबलपुर

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 भू—राजस्व संहिता 1959

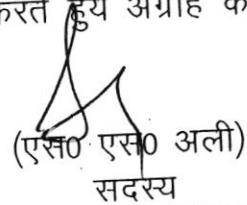
आवेदिका माननीय न्यायालय नायब तहसीलदार (केन्ट क्षेत्र) जिला कार्यालय कलेक्ट्रेट जबलपुर के प्र.क्र. ६-अ/१२-२०१७-१८ में पारित आदेश दिनांक ०८-११-२०१७ एवं रा.नि. द्वारा दिनांक ०४-१०-२०१६ को किये गये सीमांकन से परिवेदित होकर यह पुनरीक्षण याचिका माननीय न्यायालय के समक्ष निम्नांकित तथ्य एवं आधारों पर प्रस्तुत करती है।

तथ्य — प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि आवेदिका ने ग्राम कजरवारा न. ब. 505 पटवारी हल्का नं. 23 स्थित भूमि खसरा नं. २८०/२ रकवा ०.२४३ है, में से रकवा ०.१६० है, भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक ०४-०७-२००५ विक्रेता भूमि स्वामी मथुरा प्रसाद कुशवाहा से खरीदी थी। उक्त भूमि का आवेदिका ने दिनांक ०६-११-२००९ को सीमांकन कराया था जिसमें आवेदिका के स्वामित्व की भूमि में अनावेदक क्र. १ का अवैध कब्जा पाया गया था जिसे प्राप्त करने के लिये आवेदिका ने धारा २५० भू—राजस्व संहिता १९५९ के अंतर्गत कार्यवाही की थी जिसका प्रकरण क्रमांक ३२८-बी-१२१-२०१२-१३ पर दर्ज होकर माननीय न्यायालय अपर आयुक्त जबलपुर संभाग, जबलपुर के समक्ष विचाराधीन है।



न्यायालय, राजस्व मण्डल, म० प्र०, गवालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग-अ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 4749 / 2018 / जबलपुर / भूरा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकोंआदि के हस्ताक्षर
०१ -८-१८	<p>आवेदक के अधिवक्ता श्री एम० एम० मुदगल उपस्थित। उनके द्वारा यह निगरानी नायब तहसीलदार केन्ट क्षेत्र जिला कार्यालय क्लेक्ट्रेट जबलपुर के प्रकरण क्रमांक ६ / अ-१२ / २०१७-१८ में पारित आदेश दिनांक ०८.११.२०१७ एवं राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक ४.१०.१६ को किये गये सीमांकन के विरुद्ध म०प्र० भू-राजस्व संहिता १९५९ की धारा ५० के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई। निगरानी आवेदन पत्र के साथ उनके द्वारा धारा-५ का आवेदन पत्र मय शपथ पत्र के प्रस्तुत किया गया है।</p> <p>२- आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी ७ माह के विलंब से प्रस्तुत की गई है। आवेदक द्वारा म्याद अधिनियम की धारा-५ के अन्तर्गत दिये गये आवेदन में ऐसे कोई ठोस आधार नहीं दर्शाये गये हैं जिसमें विलंब माफ किया जा सके, समयावधि बाह्य प्रकरणों में दिन प्रतिदिन के विलंब का स्पष्ट एवं समाधानकारक कारण दर्शाया जाना चाहिये। आवेदक अधिवक्ता एवं आवेदक द्वारा विलंब के संबंध में कोई ठोस व स्पष्ट कारण नहीं दर्शा सके हैं। अतः निगरानी अवधि बाह्य मान्य करते हुये अग्राह की जाती है।</p>	 (एस० एस० अली) सदस्य